

SHRI JANARDHAN POOJARI: One minute, Madam. Afterwards they can raise anything. In the case of CCP shares also, if special circumstances like default in payment of dividend, arise, then, voting rights, would become available. This is the meaning.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: You are right. That is the provision. That is what I am telling you. That rate is fixed. But it can cumulate if the dividend is not given.

**STATUTORY RESOLUTION DIS-
APPROVING THE TERRORIST AND
DISRUPTIVE ACTIVITIES (PRE-
VENTION) AMENDMENT ORDI-
NANCE, 1985**

AND

**THE TERRORIST AND DISRUPTIVE
ACTIVITIES (PREVENTION)
AMENDMENT BILL, 1985—contd.**

श्री गुलाम रसूल कार : मोहतरिमा डिप्टी चेयरमैन साहिबा, जहां तक इस एक्ट का ताल्लुक है, यह आर्डिनंस की सूरत में पहले ही काश्मीर पर लागू है और अब एक फारमेलिटो के तहत पार्लिय मेन्ट के दोनों एवानों में पेश किया गया है। चाहिए यह था कि इस हालत के आन्तरेबल मेम्बरान इस एक्ट के जम्मू काश्मीर में लागू करने के बारे में या उसकी मुखालफत में कुछ कहते, लेकिन तमाम काश्मीर की सिथासत को इसमें ले आए हैं। नेशनल वॉर्कर्स को अन्दरूनी लड़ाई से, घर की लड़ाई से, वहां पर दो पार्टियां हो गई, स्पिलिट हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी मदद से उनकी गवर्नमेंट वजूद में आई। मैं शाल साहब से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की कभी यह खाहिश नहीं रही है कि हम कभी भी दूसरों को अपने साथ चलने के लिए कहें या अपने साथ चलने के लिए आमादा करें। शेख साहब का जमाना याद में लाइये। जब वहां पर उनका एक भी मेम्बर नहीं था, सारा दुनिया की जमूरियत में यह पहली मिसाल है जब हमने शेख, साहब को सरेरा उठाकर अपना लीडर माना, उनको हुकूमत सिपुर्द की। हमें इस वक्त वहां पर कौन हुकमत हैं या कौन हुकूमत आगे आने वाली होगी, इसमें नहीं जाना चाहिए। हमें

इस वक्त को अपने जैरेनजर रखना चाहिए। जहां तक घर के मेम्बरान का ताल्लुक है, यहां पर बार-बार दफा 370 का तसकरा किया जाता है। कुछ लोगों का काश्मीर के बारे में हमेशा यह रवैया रहा है कि वहां पर जो तरक्की पसंद हुकूमत हो उसकी मुखालफत की जाय। अगर आप इस दफा 370 को देखें तो आपको पता चलेगा कि कांस्टिट्यूशन में जब इस दफा को रखा गया तो उस वक्त हमारे रहनुमा पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और श्री रफी अहमद किदवाई थे। उन्होंने काश्मीर की गुरवत और काश्मीर की इकसाजी पशमान्दगी, काश्मीर की टोपोग्रेफी और काश्मीर के पास जो कम जमीन है, उन सब को पेशे नजर रखकर इस दफा को रखा। आज भी जब कुछ लोगों को मौका मिलता है तो वे इस दफा को हटाने की बात करते हैं लेकिन जहां तक हमारी पार्टी कांग्रेस का ताल्लुक है जिन्होंने इस दफा को कांस्टिट्यूशन में रखा है उन्होंने जम्मू काश्मीर के लोगों को एक कमिटमेन्ट दिया है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक कमिटमेन्ट किया था और वह कमिटमेन्ट वहां की हालत को पेशे नजर रख कर किया गया था। जम्मू-काश्मीर का अपना कांस्टिट्यूशन बना, वहां की ऐसेम्बली ने उसकी रेटिफाई किया। तमाम कन्ट्री के साथ रहने के लिए यह किया गया। कल भी जब आपने असम के बारे में अर्वाइड यहां पेश किया, हर तरफ से उसकी सराहना की गई और हौनी चाहिए। एक अच्छा कदम था। पंजाब के बारे में, असम के बारे में दफा 6 में है कि :

“Constitutional, legislative and administrative safeguards, as may be appropriate, shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.”

जब कल इस हाउस में होम मिनिस्टर ने असम के बारे में इस हद तक कि अगर हमें आईनी सूरतों में कुछ सेफ गार्ड्स वहां की जुवान, कल्चर, तहजीब और तमद्दम देना पड़े, तो हम देने के

लिये तैयार है। काश्मीर के बारे में जब यहां बात आती है तो हमने यहां देखा है कि बार-बार ऐसी ताकतों की तरफ से, ऐसी जमातों की तरफ से इस बात को बार-बार यहां हाउस में और हाउस के बाहर उठाया जाता है कि दफा 370 को हटाना चाहिए। जहां तक काश्मीर के लोगों का ताल्लुक है, काश्मीर की कांग्रेस का ताल्लुक है, हमारी प्रोग्रेसिव तबारीख का ताल्लुक है हम जहरियात के लिहाज से इस दफा को अपनी तरह से समझते हैं। हमारे लिये यह दफा रहनी चाहिए और काश्मीर के लोगों को यह हक है इस दफा को रखने का। अगर काश्मीर के लोग जम्मू और काश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग आमादा हों कि इस दफा की अब जरूरत नहीं तो हम कोई दकोका फरागुजाश नहीं करेंगे। जब हम एट पार आ जायेंगे, पंजाब की तरक्की के साथ, आम की तरक्की के साथ, दिल्ली की तरक्की के साथ, महाराष्ट्र के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारा एक छाटो सी रियासत है जिसका दारोमदार सिर्फ एथीकल्वर पर है। लिहाज में उन मेम्बरान से गुजरिश करूंगा कि वे इस दफा के सिलमिले में जब भी तकरा करते हैं तो इससे होता यह है कि हमारे दुश्मनों को मौका मिलता है और वे इन चीजों को उभाड़ते हैं और इससे अनसुन्दरी पैदा हो जाती है, मिश्रामो तौर पर हमें लगता है कि अक्सर काश्मीर में अवसरियात है, एक खास तबके, आप यकीन मानिये, जब 1947 में पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया, जब 1947 में वहां दरिन्दे आ गये तो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि हमनावर खबरदार, हम काश्मीरी हैं। काश्मीरियों को एकता का ही हिस्सा है। आज भी काश्मीर में वही लोग हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि जिन काश्मीरियों ने जेहद के नारे को ठुकराया, कुरान के नाम पर जेहद के नारे को ठुकरा दिया उनके ऊपर शक और शूबहा अपने मन में पैदा करना, मैं समझता हूं कि उनके साथ जादती होगी। मैं यकीन रखता हूं कि हमारे लोग जो हिन्दुस्तान के रहने वाले पेट्रेयट हैं, देशभक्त हैं, मोहिब्बे बान हैं हमारी मोहिब्बे बतना

एक फर्जी जमात की नहीं है। हम उम हिन्दुस्तान के लोग हैं जिनकी रहनुमाई महात्मा गांधी ने की, जिनकी रहनुमाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और जिसकी विरासत इंदिरा गांधी ने कबूल की और जिसकी विरासत आज के नौजवान लीडर राजीव गांधी ने कबूल की है। लिहाज इन जमानतों को जेहन में रखनी चाहिए जो कभी कभी सवाल उठाते हैं और खुद मुख्तारी देने के लिये जब काश्मीर का नाम आता है तो उनके दिल में घंटी बजती है। मैं आनरेबल मिनिस्टर इंचार्ज से गुजरिश करूंगा कि इस ऐक्ट को जहां तक लागू करना है, यह वक्त का तकाजा है कि काश्मीर को पंजाब, असम, मिजोरम, नागालैंड या बाकी रैस्ट आफ दि कण्ट्री की तरह नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान अभी भी काश्मीर के बारे में इंटरनेशनल फोरम में बात उठा रहा है। हाल ही में सो काल्ड काश्मीर के प्रेसीडेन्ट ने कहा कि हम शिमला मुआहिदा पर चलने के पाबंद नहीं हैं और उन्होंने अपने तौर पर डेलीगेशन भेज दिया मकबूजा काश्मीर के साथ कि काश्मीर में भी राय शुमारी होनी चाहिए। आज भी दरअंदाजी हो रही है, आज भी सरहद पर गोलियां चलाई जाती हैं। आज भी सेशंसनिस्ट्स एलीमेन्ट्स काश्मीर में हैं। आज वो इस तहरीक के मौजिद हैं कि काश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिये। जमायते इस्लामी ने वहां पर जाल बिछाया हुआ है। अपनी जमात के मुखलिफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कौंसिल, काश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हाजमी इस्लाम और इस्लाम स्टुडेंट्स आर्गनाइजेशन। यह आर्गनाइजेशन पायेकार है। इनको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है। वहां इनको बन्दूक चलाने की, बम चलाने की, हैंड-ग्रेनेड चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। 2 जुलाई, से आज तक 15 बार बम गिराये गये हैं। यह खुदा का शुक है कि कोई जखमी नहीं हुआ यह आपके वक्त में भी हुआ, कांग्रेस के दौर में भी हुआ, आज भी हो रहा है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है (व्यवधान) शाह सरकार रोकती नहीं है, यह ठीक बात है। जब एक इंटरनेशनल साजिश हो, जब सरहदों पर दुश्मन हो

[श्री गुलाम रसूल कार]

बहुत बड़ी ताकत हो, दरअंदाजी हो, पैसा मिलता हो, जब हम उनका मुकाबला करते थे माफ कीजिए, तब आप हमारे साथ नहीं थे। (व्यवधान) 27 वक्त्यात हो गये पिछले एक साल में आतिशजदगी के और वीसियों ऐंमे लोग हैं जो मरेआम खुले तौर पर यह कहते हैं कि हमारी इहलाक हिन्दुस्तान के साथ नहीं है। शाल साहब से मैं पूछना चाहता हूं वहीँसियते माँहवे वतन के इनका फर्ज था, यह जमायते इस्लाम का नाम लेकर खुलेआम कहते हैं कि हमारा एक्सपेंशन पूरा नहीं हुआ, आपने क्यों इस बात को छिपाया? उनके स्कूल चल रहे हैं, ग्रास रुट्स पर गांवों में प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल, इस जमायते इस्लाम का ताल्लुक हिन्दुस्तान का जमायते इस्लाम के साथ नहीं है, यह हिन्दुस्तान की जमायते इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यह एक अलाहिदा फोरम है और खुले तौर से पाकिस्तान के साथ होने का नारा देने हैं। कल ही 14 अगस्त, पाकिस्तान का योमेआजादी दिन है, पाकिस्तान हमारा हमसाया है, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मुलह हानो चाहिये, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिये लेकिन दिल्ली में रह कर मैं समझता हूं जैसे दिल्ली वैसे श्रीनगर में रह कर अगर कोई पाकिस्तान डे पर नारा देता है, इन चीजों को छिपाना मैं समझता हूँ कि यह कोई पेट्रॉटिज्म के लिए कोई खिदमत नहीं है। आप को खुले तौर पर कहना चाहिये कि इस किस्म के अन्सर वहां मौजूद हैं।

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : मोहतरिम मैंने अर्ज किया कि काश्मीर में हालात बदतर हैं इस वजह से वहां की सरकार को चलता किया जाए (व्यवधान)

श्री गुलाम रसूल कार : जनाबेवाला, यह इन्होंने फरमाया कि सरकार को चलता करना चाहिये। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि जब तक किसी सरकार को असेम्बली में अदमे-एहतमात हासिल है कोई भी सरकार किसी सरकार को वहां से हटा नहीं सकती है। अगर आप में ताकत हैहिम्मत है (व्यवधान)

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : दो जुलाई को असेम्बली में अदमे-एहतमात नहीं था।

श्री गुलाम रसूल कार : आइये असेम्बली में अगर आपके पास अकसरियत है। डेमोक्रेसी में आप हंगामा करना चाहते हैं, असेम्बली की कार्यवाही को रोकते हैं, यह कोई डेमोक्रेसी है। क्या यह जम्हूरियत रज निजाम है, क्या आप यह अपनी नस्लों के लिये आइंदा के लिए मिसाल बना रहे हैं कि असेम्बली को चलने नहीं देना चाहिये? (व्यवधान)

हम क्यों सपोट विदड्रा कर लें। आप चार्जशीट लाइये। आप करर्जेशन की बात करते हैं। आप क्यों नहीं चार्जशीट लाते हैं। आप प्रेजिडेंट को मेमोरेंडम क्यों नहीं देते हैं? आप पार्लियामेंट को मेमोरेंडम क्यों नहीं देते हैं, आप क्यों नहीं लोगों में जाकर के तहरीक बना लेते हैं (व्यवधान)

श्री सैयद अहमद हाशमी (उत्तर प्रदेश) : दो क्राइटेरिया नहीं हो सकते। एक डाक्टर फारुख अब्दुल्ला क्राइटेरिया और एक शाह क्राइटेरिया (व्यवधान)

श्री गुलाम रसूल कार : साहब इनके घर में फसाद हो गया, शाह साहब नेशनल कान्फेंस में जारल सेक्रेटरी थे, जालिदा शेख साहब की बेटी थी, उन्होंने एक अलाहिदा जमात बनाई। असली नेशनल कान्फेंस वो हैं। हमारा क्या कसूर है। आप घर की लड़ाई खत्म कीजिए आपस में गले मिलिये, हमें कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : डिप्टी चेयरमैन, मेरी एक अर्ज है जो इन्होंने कांग्रेस कानवेंशन में तहरीर की वो यहां पर फरमाएं (व्यवधान)

Withdraw your support. It will tumble down.

3 P. M.

श्री गुलाम रसूल कार : मोहतरिम मैं अर्ज कर रहा था, 14 अगस्त, की शाम को शाल साहब पूरी तरह इल्मी हैं अखबार पढ़ते हैं, 14 अगस्त, की शाय को वहां फतेहकदल में एक टेपल में बम

गिराया गया। टैंक की दीवार गिर गई और नुकसान पहुंचा? ये बम कहां से आते हैं। ये सरहद पार से आते हैं। . . . (व्यवधान) पहले आप करते थे, अब जमायते इस्लामी वाले करते हैं। आप राहें रास्त पर गए, वह भी राहें रास्त पर आ जायेंगे। पहले आप उनकी स्पोर्ट करते थे। आज आप राहें रास्त पर गए हम उनको भी राहें रास्त पर लाने की कोशिश करेंगे।

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : 13 महीनों में बताइये कितनों को गिरफ्तार किया किसी को पकड़ा भी? आज गुरुद्वारा बारामुल्ला में टेरॉरिस्ट्स बैठे हैं। 6 महीने से कहा जाता है वहां पर और गंगुवाल में ट्रेन में बम फटा है और फिर तीन बार काशिलाना हमला हुआ यह फारूक अब्दुल्ला पर, यह है गुलशाह सरकार। आप स्पोर्ट विद्रोह कर लीजिए?

श्री गुलाम रसूल कार : मोहतरिमा, आपको याद होगा . . . (व्यवधान) जब हम गुरुवत पालिसी की बात करते थे तब शाल साहब कहते थे कि ऐसा नहीं हो रहा है। . . . (व्यवधान) आज शाल साहब खुद कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ठीक बात है, आज आप हमारी ताईद कर लेंगे, कल आपको पब्लिक में हमारी ताईद करनी पड़ेगी। आपको हमारा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और हालात का तकाजा है, कौमी इतहाद का तकाजा है, मुल्के मोहब्बे वतन होने का तकाजा है आपको हमारे रास्ते पर चलना पड़ेगा, हमारा रास्ता कबूल करना पड़ेगा।

उपसभापति : शाल साहब आप उनको बोलने दीजिए।

SHRI GULAM MOHI-UD-DIN SH-AWL: Whenever my name is referred to, I have to reply, our only contentation is: withdraw your support and the Government will tumble down. It is a non-representative and puppet Government.

श्री गुलाम रसूल कार : मोहतरिमा, मैं अर्ज कर रहा था, शाल साहब ने हमारी हर वक्त ताईद की और मैं यह महसूस

करता हूँ कि जो बातें इन्होंने अपनी तक्रार में उठाई वह गैर जरूरी थीं। (व्यवधान)

उप सभापति : हाशमी साहब अपना नाम नहीं लिया है इसलिए आप कृपया बैठ जाइये।

श्री गुलाम रसूल कार : इस एक्ट का जहां तक ताल्लुक है बाय प्रेजिडेंशियल प्रोक्लमेशन वहां आलरेडी आर्डिनंस फाईल हो चुका है, महज इस एक्ट की महदुदियद यह है कि इस एक्ट को लागू कर रहे हैं काश्मीर के अन्दर और काश्मीर के हालात, पंजाब के हालात भी, आसाम और भिजोरम के हालात भी एक बहुआयामी मतह पर एक दूसरा मुल्क अब भी कोशिश कर रहा है। अब भी कन्प्यूजन पैदा कर रहा है। काश्मीर के बारे में रायशुमारी के बारे में शिमला और ताशकन्द एग्रीमेंट के बारे में, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वस वहमियते मोहब्बे वतन से आपको हमारा साथ देना चाहिए और ऐसे अनासिर का हमें सियासी मतह पर भी मुकाबला करना पड़े जमायते इस्लामी का और ऐसे अनामर का जिन मनफी सियासत हो यह ही सही रास्ता है, यह सही रास्ता अख्तियार करना चाहिए, मैं इस एक्ट की पुरजोर ताईद करता हूँ। साथ ही यह कहना चाहता हूँ। मर्कजी सरकार से कि पंजाब में आपने एकोर्ड किया है, यह बहुत खुशी की बात है, बलकम, लेकिन साथ ही आपने कहा कि वहां पर कोच फैक्ट्री होगी और दस हजार लोगों को काम मिलेगा। आसाम में आपने एकोर्ड किया, वहां दो फैक्ट्रियां कायम की। हम फैक्ट्रियां नहीं चाहते हैं। साथ मैं एक कन्प्यूजन है हमारे जेहन में, 40 साल यही हमने आपके साथ फस्टेशन किया 40 साल तक आप रेल को काश्मीर नहीं लाये, श्रीनगर तक आखिर लोगों में एक किस्म का कन्प्यूजन पैदा होता है। डेढ़ अरब रुपया आपने कोच फैक्ट्री में लगाया पंजाब में मैं नहीं कहता डेढ़ नहीं तीन अरब रुपया आपको खर्च करना चाहिए मैं कहता हूँ दस हजार लोगों को नहीं बीस हजार लोगों को काम दे दीजिए, लेकिन क्या काश्मीरियों का यह हक नहीं कि आप हमें रेल दे दें?

[श्री गुलाम रसूल कार]

रेल आने से कौमी इकज्जहती में बढ़ावा होगा। तहज्जब एक दूसरे की मिलती-जुलती है, कल्चर मिलता-जुलता है। कन्स्यूजन यही दूर हो जाता है। आपने वहां पंजाब में पांच हजार लोगों को काम देने के लिए सी०आर०पी० में या बी०एस०एफ में भर्ती का एलान किया। यह बहुत खुशी की बात है, खुशामदीय करते हैं, बल्लम करते हैं लेकिन काश्मीर रियासत में अगर आप सिर्फ डेढ़ हजार दो हजार लोगों को मेन सिटी में लाकर उनको मुलाज्जमत देकर, जहां दूसरी रियासतों में लगाकर वहां के खसूमी तौर पर बचाये दहल यह बात कहना चाहता हू कि वहां बेकारी है, तालीम याफता मुसलमान बेकार है, मुसलमानों में ग्रेजुएट हैं, एम० ए० हैं, एम०एस०सी० है। अब आप जराए महदुद देखते हैं...

तो लाजमी तौर पर जब उनके इक्तसादी ममायल हल नहीं होने हैं, तो लाजमी तौर पर एक फस्ट्रेगन आ जाती है। जब फस्ट्रेगन आ जाती है, तो वह ऐसे काम कर पाते हैं कि वह बुरी राह पर पड़ते हैं, वह गलत सियासत में पड़ते हैं, वह गलत हाथों में पड़ते हैं।

आप काश्मीर को पंजाब के साथ मिलाइये आप काश्मीर को असम के साथ मिलाइय। जमे आपने असम का मसला हल कर दिया, आप असम में दो फैक्टरियां कायम कर रहे हैं, आप पंजाब में कोच फैक्टरी कायम कर रहे हैं, आप हजारों लोगों को वहां मुलाज्जमत में भरती कर रहे हैं।

आरिफ साहब, यह वही काश्मीरी हैं जिन्होंने 1947 में कहा था—हमलावर खबरदार, हम काश्मीरी होते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यकीनन।

श्री गुलाम रसूल कार : आज क्यों वहां आवाजें उठ रही हैं? आज इस वजह से वहां आवाजें उठ रही हैं, आवादा बढ़ रही है, तालीम याफता बेकारी बढ़ रही है। जो हमारे मरकजी दफातिर है,

वहां आप देख लीजिए कि उनमें कौन भरती है, कौन से फिरके के लोग हैं। एक परमेट भी वहां सीट वाला मुलाज्जमत में नहीं है, सरकारी ईफातिर में मुलाज्जमत में नहीं है, नेशनलाईज्ड बैंक में और जब यह सुरतेहाल हो, तब नौजवानों में फस्ट्रेगन पैदा हो जाती है।

मेरे पैट्रियाटिज्म को कोई चेलेंज नहीं कर सकता।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यकीनन।

श्री गुलाम रसूल कार : मैंने दो बार पाकिस्तानियों का मुकाबला करके गोली खाई है लेकिन मैं अलग एगान कहना चाहता हूँ, जब तक आप काश्मीर में श्रीनगर तक रेल नहीं लाते, जब तक आप काश्मीर को यहां के मेन-स्ट्रीम में, मुलाज्जमत में इन्वाल्व नहीं करते, फौज में इन्वाल्व नहीं करते, सी०आर०पी० में भरती नहीं करते, रेल के महकमों में भरती नहीं करते उनको उनका पुरा हक नहीं देने, तो एक किस्म की फस्ट्रेगन पैदा हो जाती है।

मैं आपसे गुजारिश करता हूँ आपकी वसातत से, अपने महबूब प्राइम मिनिस्टर मे, नौजवान प्राइम मिनिस्टर मे कि वह काश्मीर की तरफ तवज्जह दें, वहां कारखाना खुलना चाहिए, जो कुछ आपने आज तक किया है, हम मरहूने मिन्नात हैं मरकजी सरकार के कि आपने काफी पैसे हमें दिय, हमने बिजली पैदा की, हमने गांव-गांव सड़कें पहुंचाई हमने पुल बनाय, कालेज खोले, दो यूनिवर्सिटीज और दो मेडिकल कालेज खोले, लेकिन बेकारी है, यहां तालीम-याफता बेकारी है। उसको कम करने की तरफ तवज्जह दीजिए और यकीन जानिये कि काश्मीर आपका है, काश्मीर आपका रहेगा, हमेशा रहेगा। इसके साथ ही मैं डम एकट की ताईद करता हूँ।

†[شدری غلام رسول کار (نامزد):

محترمہ ذہنی چھنرمہن صاحبہ -
جہاں تک اس ایکٹ کا تعلق ہے یہ
آرڈیننس کی صورت میں پہلے ہی
کشمیر پر لاگو ہے اور اب ایک فارملٹی
کے تحت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں
میں پیش کیا گیا ہے - چاہئے یہ
تھا کہ اس ہاؤس کے آنریبل ممبران
اس ایکٹ کے جموں کشمیر پر لاگو
کرنے کے بارے میں یا اسکی مخالفت
میں کچھ کہتے - لیکن تمام کشمیر
کی سیاست کو اسمیں لے آئے ہیں -
نیشنل کانفرنس کی اندرونی لڑائی
سے - کھر کی لڑائی سے وہاں پر دو
پارٹیاں ہوگئیں اسپلٹ ہوگیا - اس
میں کوئر شک نہیں کہ ہماری مدد
سے ان کی گورنمنٹ وجود میں آئی -
میں شال صاحب سے کہنا چاہتا
ہوں کہ کانگریس کی کبھی یہ خواہش
نہیں رہی ہے کہ ہم کبھی بھی
دوسروں کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے
کہیں یا اپنے ساتھ چلنے کے لئے آمادہ
کریں - شیخ صاحب کا زمانہ یہاں
میں لایئے جب وہاں پر ان کا ایک
بھی ممبر نہیں تھا - ساری دنیا کی
جمہوریت میں یہ پہلی مثال ہے
جب ہم نے شیخ صاحب کو سر اٹھا
کر اپنا لودر مانا - ان کو حکومت
مپرہ کی - مہر اسوقت وہاں پر
کون حکومت ہے یا کون حکومت آئے

آنے والی ہوگی اسمیں نہیں جانا
چاہئے - ہمیں اسوقت کو اپنے زیر نظر
رکھنا چاہئے - جہاں تک ادھر کے
ممبران کا تعلق ہے یہاں ہر بار بار
دفعہ ۳۷۰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے -
کچھ لوگوں کا کشمیر کے بارے میں
موشہ یہ رویہ رہا ہے کہ وہاں پر
جو ترقی پسند حکومت ہو اس کی
مخالفت کی جائے - اگر آپ اس
دفعہ ۳۷۰ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ
چلے گا کہ کانستی ٹیوشن میں جب
اس دفعہ کو رکھا گیا تو اسوقت ہمارے
وہلما پلڈت جواہر لال نہرو - مولانا
ابوالکلام آزاد - سردار پتیل اور شری
رفیع احمد قدوائی تھے انہوں نے
کشمیر کی فورت اور کشمیر کی
اقتصادی پماندگی کشمیر کی تریو
کرافی اور کشمیر کے پاس جو کم
زمین ہے ان سب کو پیش نظر رکھ
کر اس دفعہ کو رکھا - آج بھی جب
کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے تو وہ
اس دفعہ کو ہٹانے کی بات کرتے
ہیں - لیکن جہاں تک ہماری پارٹی
کانگریس کا تعلق ہے جملہوں نے اس
دفعہ کو کانستی ٹیوشن میں رکھا ہے
انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو
ایک کمتیہلت دیا ہے - پلڈت
جواہر لعل نہرو نے ایک کمتیہلت
دیا تھا اور وہ کمتیہلت وہاں کی
ہالت کو پیش نظر رکھ کر رکھا گیا
تھا - جموں کشمیر کا اپنا کانستی ٹیوشن
بنا وہاں کی اسمبلی نے اسکو وثیفائی

[شہری غلام رسول کار]

کیا - تمام کلتوری کے ساتھ دہلے کے لئے یہ کیا گیا -

کل بھی جب آپ نے آسام کے بارے میں اگرت یہاں پیش کیا - ہر طرف سے اسکی سراہنا کی گئی اور ہونی چاہئے - ایک اچھا قدم تھا - پنجماب کے بارے میں آسام کے بارے میں دفعہ ۶ میں ہے کی...

"Constitutional, legislative and administrative safeguards, as may be appropriate, shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people."

جب کل ہاؤس میں ہوم منسٹر نے آسام کے بارے میں اس حد تک کہ اگر ہم آئینلی صورتوں میں کچھ سیف گارڈس رہاں کی زبان کچھ - تہذیب اور تمدن دینا پڑے تو ہم دہلے کے لئے تیار ہیں - کشمیر کے بارے میں جب یہاں بات آتی ہے تو ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ بار بار ایسی طاقتوں کی طرف سے ایسی جماعتوں کی طرف سے اس بات کو بار بار یہاں ہاؤس میں اور ہاؤس کے باہر اٹھایا جاتا ہے کہ دفعہ ۳۷۰ کو ہٹانا چاہئے - جہاں تک کشمیر کے لوگوں کا تعلق ہے - کشمیر کی کانگریس کا تعلق ہے - ہمارے پروگریسیو تواریخ کا تعلق ہے - ہم ضروریات کے لحاظ سے اس دفعہ کو اپنی طرح سے سمجھتے ہیں - ہمارے لئے یہ دفعہ

دہلی چاہئے اور کشمیر کے لوگوں کو یہ حق ہے کہ اس دفعہ کو رکھلے گا - اکثر کشمیر کے لوگ جموں اور کشمیر کے لوگ لداخ کے لوگ آمادہ ہوں کہ اس دفعہ کی اب ضرورت نہیں تو ہم کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے - جب ہم اہمیت پار آجائیڈگے ہلجباب کی ترقی کے ساتھ - آسام کی ترقی کے ساتھ - دلی کی ترقی کے ساتھ - مہاراشٹر کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن میں - ہماری ایک چھوٹی سی ریاست ہے جسکا دارو مدار صرف ایگریکلچر پر ہے - لہذا میں ان ممبران سے گزارش کرونگا کہ وہ اس دفعہ کے سلسلے میں جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے دشمنوں کو موقع ملتا ہے اور وہ اس چیز کو ابھارتے ہیں اور اس سے ان سہیتیلٹی پیدا ہو جاتی ہے سیاسی طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اکثر کشمیر میں اکثریت ہے - ایک خاص طبقہ کی - آپ یقین مانتے جب ۱۹۴۷ میں پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا - جب ۱۹۴۷ میں وہاں درندے آئے تو کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ حملہ آور خیردار ہم کشمیری ہیں - یہ کشمیریوں کی ایکٹا کا ہی حصہ ہے - آج بھی کشمیر میں وہی لوگ ہیں - ہمیں یہ سوچنا چاہئے جن کشمیریوں نے جہاں کے نعرہ کو تھکوا دیا - قرآن کے نام پر جہاں کے نعرہ کو تھکوا دیا ان کے اوپر شک و شبہہ اپنے

من میں پیدا کرنا - میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی - میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہندوستان کے رہنے والے وہ پیٹریوٹ ہیں - محب وطن ہیں - ہماری محب وطنی ایک فرضی جماعت کی نہیں ہے - ہم اس ہندوستان کے لوگ ہوں جن کی رہنمائی مہاتما گاندھی نے کی - جس کی رہنمائی پندت جواہر لعل نہرو نے کی اور جس کی وراثت اندرا گاندھی نے قبول کی اور جن کی وراثت آج کے نوجوان لیڈر راجدو گاندھی نے قبول کی ہے - لہذا ان جماعتوں کو ذہن میں رکھنا چاہئے جو کبھی کبھی سوال اٹھاتے ہیں اور خود مستعدی دینے کے لئے جب کشمیر کا نام آتا ہے تو ان کے دل میں گہلٹی بھرتی ہے - میں آنریبل ممبر انچارج سے گزارش کرنا کہ اس ایجنٹ کو جہاں تک لاگو کرنا ہے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ کشمیر کو پنجاب آسام - میزورم - ناگالینڈ یا باقی ریاست آف دی کنتری کی طرح نہیں دیکھنا چاہئے - پاکستان ابھی بھی کشمیر کے بارے میں انٹرنیشنل فورم میں بات اٹھا رہا ہے - حال ہی میں سو کالڈ کشمیر کے ایک پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم شملہ معاہدہ پر چلنے کے پابند نہیں ہیں اور انہوں نے اچھے طور پر قبائلیکیشن بھیج دیا - مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کہ کشمیر میں بھی رائے شماری ہونی چاہئے -

آج بھی دراندازی ہو رہی ہے - آج بھی اسٹیمسٹ ایجنٹ کشمیر میں ہیں آج وہ اس تحریک کے موجد ہیں کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہئے - جماعت اسلامی نے وہاں پر جال بچھایا ہوا ہے - اپنی جماعت کے مختلف اسلامک رولیشنری کونسل کشمیر لبریشن فرنٹ - ہارمین اسلام - اور اسلام اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن برائے کار ہیں - ان کو باقاعدہ تربیت ملتی ہے وہاں ان کو بددوق چلانے کی ہم چلانے کی ہیڈ کوارٹر چلانے کی تربیت ملتی ہے - ۲ جولائی سے آج تک پندرہ بار ہم گولے گئے ہیں یہ خدا کا شکر ہے کوئی زخمی نہیں ہوا - یہ آپ کے وقت میں بھی ہوا کانگریس کے دور میں بھی ہوا - آج بھی ہو رہا ہے - اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے (مداخلت) شاہ سرکار روکتی نہیں ہے - یہ تھیک بات ہے جب ایک انٹرنیشنل سازش ہو - جب سرحدوں پر دشمن ہو بہت بڑی طاقت ہو - دراندازی ہو - پیسہ ملتا ہو - جب ہم ان کا مقابلہ کرتے تھے معاف کیجئے تب آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے (مداخلت) ۲۷ واقعات ہو گئے پچھلے ایک سال میں آتشزدگی کے اور بیسیوں ایسے لوگ ہیں جو سرعام کولہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الحاق ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے - شال صاحب سے

[شرعی غلام رسول کار]

میں پوچھنا چاہتا ہوں بے حیثیت
مذہب وطن کے ان کا فرض تھا - یہ
جماعت اسلامی کا نام لے کر کھلے عام
کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسٹینشن پروگرام
نہیں ہوا - آپ نے بیوں اس بات کو
چھپایا - ان کے اسکول چل رہے ہیں -
گراس روٹس پر گاؤں میں پروانہ دی
اسکول - مڈل اسکول - ہائی اسکول -
اس جماعت اسلامی کا تعلق ہندوستان
کی جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں
ہے - یہ ہندوستان کی جماعت اسلامی
کا حصہ نہیں ہے - یہ ایک علیحدہ
فورم ہے اور کھلے طور پر پاکستان کے
ساتھ ہونے کا نعرہ دیتے ہیں - کل
ہی ۱۴ اگست جمعہ پاکستان کا یوم
آزادی کا دن ہے - پاکستان ہمارا
ہمسایہ ہے - ہم چاہتے ہیں پاک-تان
کے ساتھ ہماری صلح ہونی چاہئے -
ہم چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ
ہماری دوستی ہونی چاہئے - لیکن
یہاں دلی میں رہ کر میں سمجھتا
ہوں جیسے دلی ویسے سری نگر میں
رہ کر اگر کوئی پاکستان قے پر نعرہ
دیتا ہے - ان چیزوں کو چھپانا میں
سمجھتا ہوں پھر توڑنے کے لئے کوئی
خدمت نہیں ہے - آپ کو کھلے طور
پر کہنا چاہئے کہ اس قسم کے عنصر
وہاں موجود ہیں -

[شرعی غلام معنی الدین شال :]

مختصر - میں نے عرض کیا کہ کشمیر

میں حالات بدتر ہیں اسوجہ سے
وہاں کی سرکار کو چاہتا کیا جائے -
... (مداخلت) ...

[شرعی غلام رسول کار :]

انہوں نے فرمایا کہ سرکار کو چلنا کرنا
چاہئے - میں آپ کو یہ کہنا چاہتا
ہوں کہ جب تک کسی سرکار کو اسمبلی
میں عدم اعتماد نہیں حاصل ہے
کوئی بھی سرکار کسی سرکار کو وہاں
سے ہٹا نہیں سکتی ہے - اگر آپ
میں طاقت ہے ہمت ہے ...

[شرعی غلام معنی الدین شال :]

دو جولائی کو اسمبلی میں عدم اعتماد
نہیں تھا -

[شرعی غلام رسول کار :]

میں اگر آپ کے پاس اکثریت ہے -
ڈیموکریسی میں آپ حکامہ کرنا
چاہتے ہیں - اسمبلی کی کارروائی
کو روکتے ہیں - یہ کوئی ڈیموکریسی
ہے - کیا یہ جمہوریتی نظام ہے - کیا
آپ یہ اپنی نسلوں کے لئے آئندہ کے
لئے مثال بنا رہے ہیں کہ اسمبلی کو
چلنے نہیں دینا چاہئے... (مداخلت)
... ہم کیوں سپورٹ دے کر لیں -
آپ چارج شیٹ لائیے - آپ کرپشن
کی بات کرتے ہیں - آپ کہیں نہیں
چارج شیٹ لاتے ہیں - آپ پریزیڈنٹ
کو میمورنڈم کیوں نہیں دیتے ہیں -
آپ پاریلیمنٹ کو میمورنڈم کیوں نہیں

دیتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں لوگوں
میں جا کر کے تحریک دیا لیتے
ہوں.... (مداخلت)....

شری - ہد احمد ہاشمی : دو

کرائیڈریا نہیں ہو سکتے - ایک ڈانڈر
فاروق عبداللہ کرائیڈریا اور ایک شاہ
کرائیڈریا.... (مداخلت)....

شری غلام رسول کار : صاحب ان

کے گھر میں فساد ہو گیا - شاہ صاحب
نیشنل کانفرنس میں جنرل سکریٹری
تھے خالدہ شیخ صاحب کی بیٹی
تھی انہوں نے ایک علیحدہ جماعت
ہدائی - اعلیٰ نیشنل کانفرنس وہ ہے -
ہمارا کیا تصور ہے آپ گھر کی لڑائی
ختم کیجئے آپ میں گلے مانگے -
ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے.....
(مداخلت).....

شری غلام محی الدین شال : قیچی

چھوڑیں - میری ایک عرض ہے کہ
انہوں نے کانگریس کمونشن میں فقیر
کی وہ یہاں پر فرمائیں.... (مداخلت)

....Withdraw your support. It will
tumble down.

شری غلام رسول کار : مستحضرہ -

میں عرض کر رہا تھا کہ ۱۲ اگست
کی شام کو شال صاحب کو پوری
طرح علم ہے - اخبار پڑھتے ہیں -
۱۲ اگست کی شام کو وہاں فتح کدل
میں ایک ٹیمپل میں بم گرایا گیا -
ٹیمپل کی دیوار گئی اور نقصان

پہنچا - یہ بم کہاں سے آتے ہیں....
(مداخلت).... پہلے آپ کرتے تھے اب
جماعت اسلامی والے کرتے ہیں - آپ
راہ راست پر آئے - وہ بھی راہ راست
پر آجائیں گے - پہلے آپ ان کو سپورٹ
کرتے تھے - آپ راہ راست پر آئے -
ہم ان کو بھی راہ راست پر لانے کی
کوشش کریں گے -

شری غلام محی الدین شال : ۱۳

مہیڈوں میں ہتھیائے کتاؤں کو گرفتار
کیا گیا کسی کو پکڑا بھی آج گورنور
بارہ موانہ میں تھوڑی سی ہتھی
چھ مہیڈوں سے کہا جاتا ہے وہاں پر
اور کلنگوال میں تین میں بم پھٹا
ہے اور پھر تین ہار قاتلانہ حملہ ہوا
فاروق عبداللہ پر - یہ ہے کل شاہ
سرکار - آپ سچوٹس و قرا کر لہجئے -

شری غلام رسول کار : مستحضرہ -

آپ کو یاد ہوگا.... (مداخلت)....
جب ہم غربت پالیسی کی بات کرتے
تھے تب شاہ صاحب کہتے تھے کہ
اسے نہیں ہو رہا ہے.... (مداخلت)
.... آج شال صاحب خود کہہ رہے
ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے - ٹھیک بات
ہے آج آپ ہماری تائید کر لینگے کل
آپ کو پبلک میں ہماری تائید کرنی
پڑے گی - آپکو ہمارا راستہ اختیار
کرنا پڑے گا - اور حالات کا تقاضا ہے -
قومی اتحاد کا تقاضا ہے - ملک کا
مستحضر وطن ہونے کا تقاضا ہے آپکو

[شری غلام رسول کار]

ہمارے راستے پر چالنا پڑیگا - ہمارا
راستہ قبول کرنا پڑیگا -

ذہنی چیمبرہن : شال صاحب

آپ انکو بولنے دیجئے -

SHRI GULAM MOHI-UD-DIN
SHAWL: Whenever my name is re-
ferred to, I have to reply. Our only
contention is; withdraw your support
and the Government will tumble
down. It is a non-representative and
puppet Government.

شری غلام رسول کار : ہندوستان

میں عرض کر رہا تھا - شال صاحب
نے ہماری ہر وقت تائید کی - اور
میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو
باتیں انہوں نے اپنی تقریر میں
انہائیں وہ غیر ضروری تھیں -
.... (مداخلت)

ذہنی چیمبرہن : ہاشمی صاحب

اپکا نام نہیں لیا ہے اسلئے آپ کو یہاں
بھیجا جائیگا -

شری غلام رسول کار : اس ایکٹ

کا جہان تک تعلق ہے بائی پریویژنل
پروکلیمیشن وہاں آلبرٹی آرڈیننس
فائل ہو چکا ہے - محض اس
ایکٹ کی محدودیت یہ ہے کہ اس
ایکٹ کو لاگو کر رہے ہوں کشمیر کے اندر -
اور کشمیر کے حالات پنجاب کے حالات بھی
آسام اور میوزورم کے حالات بھی ایک
بہو آسامی سطح پر ایک دوسرا

ملک اب بھی کوشش کر رہا ہے -
اب بھی کلفوزن پیدا کر رہا ہے -
کشمیر کے بارے میں - رائے شماری
کے بارے میں - شملہ اور تاشقند
اکریمنٹ کے بارے میں میں آپ سے
گزارش کرتا ہوں کہ بدعشیت
محب وطن کے آپکو ہمارا ساتھ دینا
چاہئے اور ایسے عناصر کا ہمیں
سیاسی سطح پر مقابلہ کرنا پڑے -
جماعت اسلامی کا اور ایسے عناصر کا
جانکی منفی سیاست ہو یہ ہی صحیح
راستہ ہے - یہ صحیح راستہ اختیار کرنا
چاہئے - میں اس ایکٹ کی پرزور تائید
کرتا ہوں - ساتھ ہی یہ کہنا
چاہتا ہوں مرکزی سرکار سے کہ
پنجاب میں آپ نے اکرار کیا ہے -
یہ بہت خوشی کی بات ہے - ویکم-
لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ وہاں
پر کوچ فیکٹری ہوگی اور وہاں پر
دس ہزار لوگوں کو کام ملے گا - آسام
میں آپ نے اکرار کیا وہاں دو
فیکٹریاں قائم کیں - ہم فیکٹریاں
نہیں چاہتے ہیں - ساتھ میں ایک
کلفوزن ہے ہمارے ذہن میں - ۲۰
سال پہلے ہم نے آپ کے ساتھ فرسٹریشن
کیا ۲۰ سال تک آپ ریل کو کشمیر
نہیں لائے سری نگر تک - آخر لوگوں
میں ایک قسم کا کلفوزن پیدا ہوتا
ہے - قیصرہ ارب روپیہ آپ نے کوچ
فیکٹری میں لگایا پنجاب میں -
میں نہیں کہتا - قیصرہ نہیں تھیں
ارب روپیہ آپ کو خرچ کرنا چاہئے

میں کہتا ہوں دس ہزار لوگوں کو نہیں بیس ہزار لوگوں کو کام دیدیجئے لیکن کہا کشمیریوں کو یہ حق نہیں کہ آپ ہمیں ریل دیدیں - ریل آنے سے قومی یکجہتوں میں بڑھوا ہوگا - تہذیب ایک دوسرے کی ملتی جلتی ہے - کلچر ملتا جلتا ہے - کلفیورن بھی دور ہو جاتا ہے - آپ نے وہاں پلجاب میں ہانچ ہزار لوگوں کو کام دیلے کے لئے سی - آر - پی - میں رہا بی - ایس - ایف - میں بھرتی کا اعلان کیا - یہ بہت خوشی کی بات ہے - خدشہ آمیز کہتے ہیں - ویلکم کہتے ہیں لیکن کشمیر ریاست میں اگر آپ صرف ڈیڑھ ہزار لوگوں کو مین سٹی میں لا کر انکو ملازمت دے کر جہاں دوسری دیاستوں میں لگا کر وہاں کے خصوصی طور پر بھانکے دھل پتے بات کہنا چاہتا ہوں وہ وہاں بیکاری ہے - تعلیم یافتہ مسلمان بیکار ہیں - مسلمانوں میں گریجویٹ ہیں ایم - اے - ہیں ایم - ایس - سی - ہیں - جب آپ فرائع محدود دیکھتے ہیں تو لازمی طور پر جب ان کے اقتصادی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو لازمی طور پر ایک فرسٹریشن آجاتی ہے - جب فرسٹریشن آجاتی ہے تو وہ اسے کام کرتے ہیں کہ وہ بڑی راہ پڑتے ہیں - وہ غلط سیاست میں پڑتے ہیں - غلط ہاتھوں میں پڑتے ہیں -

آپ کشمیر کو پلجاب کے ساتھ ملائے - جیسے آپ نے آسام کا مسئلہ حل کر دیا - آپ آسام میں دو فیکٹریاں قائم کر رہے ہیں آپ ہزاروں لوگوں کو وہاں ملازمت میں بھرتی کر رہے ہیں -

عارف صاحب یہ وہی کشمیری ہیں جنہوں نے ۱۹۴۷ میں کہا تھا حملہ درخبردار ہم کشمیری ہوتے ہیں -

شری عارف محمد خان : یقیناً -

شری غلام رسول کار : آج کہوں

وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں - آج اس وجہ سے وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں - آبادی بڑھ رہی ہے - تعلیم یافتہ بیکاری بڑھ رہی ہے - جو ہمارے مرکزی دفاتر ہیں وہاں آپ دیکھ لہجئے کہ ان میں کون بھرتی ہے کونسے فرقہ کے لوگ ہیں - ایک پرسنلٹ بھی وہاں سیٹ والا ملازمت میں نہیں ہیں - سرکاری دفاتر میں ملازمت میں نہیں ہیں - نیشنلائزڈ بکنس میں - اور جب یہ صورتحال ہو تب نوجوانوں میں فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے -

میرے پیئرپاترزم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا -

شری عارف محمد خان : یقیناً -

شری غلام رسول کار : میں نے دو

بار پاکستانیوں کا مقابلہ کر کے کولی

[شری غلام رسول گار]

کہانی ہے - لیکن میں علی الاعلان
کہتا چاہتا ہوں جب تک آپ کشمیر
میں سری نگر تک دھل نہیں لاتے
جب تک آپ کشمیر کو یہاں کے میں
استوریم میں ملازمت میں انوالو
نہیں کرتے - فوج میں انوالو نہیں
کرتے - سی - آر - پی - میں بھرتی
ہوئے کرتے - ریل کے محکمے میں
بھرتی نہیں کرتے انکو انکا پورا حق
نہیں دیتے تو ایک قسم کی
فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے -

میں آپ سے گزارش کرتا ہوں -
آپ کی وساطت سے اپنے محبوب
پروانہ منسٹر سے - نوجوان پروانہ منسٹر
سے کہ وہ کشمیر کی طرف توجہ
دیں وہاں کارخانہ کھلنا چاہئے -
جو کچھ آپ نے آج تک کیا ہے ہم
مہروں منت ہیں مرکزی سرکار کے کہ
آپ نے کافی پیسے ہمیں دیئے -
ہم نے بھلی پیدا کی - ہم نے
گاؤں گاؤں سڑکیں پھیلوائیں - ہم نے
بل بلائے ہم نے کالج کھولے - دو
یونیورسٹیز اور دو میڈیکل کالج کھولے لیکن
بیکاری ہے - وہاں تعلیم یافتہ بیکاری
ہے - اسکو کم کرنے کی طرف توجہ
دیجئے اور یقین جانئے کہ کشمیر
آپکا ہے - کشمیر آپکا رہے گا - ہمیشہ
رہے گا - اسکے ساتھ ہی میں اس
ایکٹ کی تائید کرتا ہوں -]

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil
Nadu): Madam Deputy Chairman,

India has completed 38 years of in-
dependence only a few days back and
as a citizen of this great country I am
one and second to none in expressing
my total sympathy and solidarity with
the feeling that the unity and inte-
grity of the country comes foremost
and to this end if even some strong
measures like this Bill have to be
brought on the statute book, I think
everyone of us should welcome it.
Only last year we discussed *in extenso*
when the original Bill came before us.
No doubt there were differences of
opinion on the term 'terrorism' which
was expressed in the original Bill be-
cause it was all-encompassing in
nature and under this anybody or
everybody can be described as a ter-
rorist. But be that as it may, the
Home Minister at that time gave a
very responsible reply and the Bill is
now on the Statute book. What this
Bill seeks to achieve is only a limited
amendment, that it should be extended
to the State of Jammu and Kashmir.
I don't think that there should be so
much of difference of opinion about
extending our support. I fail to agree
with the other opposition Members
who have opposed this Bill...

SHRI PARVATHANENI UPEND-
RA (Andhra Pradesh): You are not
opposition. Why do you call 'other
Opposition Members'?

SHRI R. RAMAKRISHNAN: That
again is a matter of opinion whether
we are Opposition. I would like to tell
Mr. Upendra, Opposition does not
mean only having to oppose every-
thing and any thing for the sake of
opposition.

Anyway, now I have got my own
reservations about this having been
brought as an Ordinance particularly
when the Government knew that the
Parliament Session was only a few
days away, rather round the corner,
and they could have taken all the
necessary steps to get the concurrence
of the State Government and they
could have well brought straightway
a Bill before Parliament and not by
way of an Ordinance. This is the same

trend which is there in the Central Government as well as in many State Governments which I think is not a healthy one.

Whenever a Legislature or Parliament is in session or is going to be in session, the Government can always wait for a few days and bring forward the concerned legislation in a right royal manner and get the approval of all concerned.

There are so many exchanges of views here. Madam, about the happenings in Jammu and Kashmir. I will not add to the controversy or pour any oil over it. But there is definitely a case for a reference to this article, that is, article 370, and there is definitely a need to see whether this Bill encroaches on the rights of the States. But the Central Government has already constituted the Sarkaria Commission and I think that will be the more appropriate forum to discuss these larger issues.

Coming to this particular Bill, Madam, I would like to join others in condemning terrorism wherever and in whatever form it may be there. Only recently, we have seen the unfortunate episodes in Punjab coming to an end because of the bold and pragmatic decision taken by the Prime Minister in having an accord with Sant Longowal. While welcoming this and also the recent accord which has been arrived at with regard to the Assam problem, I would like to say that this type of give-and-take across-the-table agreements should become a healthy precedent to solve the other problems within our country and also with our neighbours.

Madam, this morning, my honourable colleague and friend, Shri R. Mohanaragam, was making a Special Mention about the unfortunate happenings in Sri Lanka which have led to the near collapse of the Ehimpu talks. Why I am bringing in the Sri Lankan issue while discussing the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Amendment Bill, I would like to tell the Minister, is that State terrorism should also be stopped, in whatever

form it may be there or in whatever manner it may be resorted to. I think the Government of India, through its delegation at the UN last year—I think Mr. Bhandare was the representative there—had condemned State terrorism and it is rather unfortunate that, when things are coming to a near solution, some hawks in the Sri Lanka Government are trying to disrupt the atmosphere which has led to a considerable loss of face for both the sides and, more than that, it has created a very unhappy situation. You all would have seen the sordid reports of as many as 500 people having been killed, after having been dragged out of their houses, and of children being killed and of Women being raped and, Madam the atrocities which are going on there for the last one year against the innocent Tamils in Sri Lanka have served to give a new fillip in the name retaliatory attack and this should be wholly condemned one and all. Though Delhi is far away from the Capital of Sri Lanka, the fall-out is very immediate in Tamil Nadu and tempers are running high there and I would like to take this opportunity of requesting through you, Madam, the Home Minister and the Minister of State for Home Affairs who is here and also appeal to our honourable Prime Minister to use his good offices even at this late stage in seeing that the situation becomes normal and the talks go on and the whole thing comes to a very satisfactory end as in other places.

Now, Madam, coming to the question of the unlicensed arms factories in the country, there are so many newspaper reports that in U.P., Bihar and in other places, a number of unlicensed arms factories have sprung up and these are the exact places which give arms of the terrorist wherever they are and added to this we have Pakistan as our neighbour which is encouraging the forces of destabilization in our country and we have a real problem on our hands. As my friend Mr. Kapil Verma was saying this morning large-scale gun-running is taking place on the borders,

[Shri R. Ramakrishnan]

whether it is from Pakis'an or through Nepal or even through the North-Eastern borders. Sir, this is a problem which the Government of India, particularly the Ministry of Home Affairs, should tackle and they should see that the supply of arms to the terrorists is stopped. Unfortunately, even in Delhi, full facts have not come to light. But the unfortunate murder of Shri Lalit Maken and his wife is also linked to the terrorists and I think that it is a right step that the Government of India has taken in bringing forward this Bill and putting it on the Statute Book.

Before I conclude, Madam, I would only like to make only one more point and it is this that the Central Government should ensure that these strong Bills which are there on the Statute Book are not misused against political rivals or political enemies. No doubt, some members from the Treasury Benches have also given statistics to say that even under the NSA not even a single person has been booked and that even this Act will not be used against political rivals or political enemies. But it is the bounden duty of the Central Government to see that even the State Governments do not take advantage of any loopholes in this sort of legislation to see that they settle scores with political rivals, because that is not the object for which the Bill has been brought.

With these words, I support and welcome this Bill. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Keshavprasad Shukla.

श्री केशव प्रसाद शुक्ल (मध्य प्रदेश) :
उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 1985 का समर्थन करता हूँ। आतंकवादी गतिविधियों से हमारे देश को कितना नुकसान हुआ है यह सबको मालूम है। हमने पंजाब में इसका

भयंकर तांडव नृत्य देखा है जहाँ पर हजारों निरीह निरपराध लोगों की हत्याएँ हुई हैं और उसी कड़ी में हमारी महान नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी का बलिदान भी आता है। ऐसी गतिविधियों से देश को खतरा है, देश की एकता और अखंडता को खतरा है और उगको रोकना सरकार का पगम कर्तव्य है। इसी से इस आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पिछले सत्र में लोक सभा और राज्यसभा दोनों में एक विधेयक पास किया गया। आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक पास किया गया लेकिन उसको उस समय कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। इसलिए यह विधेयक संशोधन के रूप में लाया गया है। यह बहुत छोटा सा विधेयक है। इसको बहुत तूल दिया गया है और इसमें बहुत से राजनीतिक मसले लाए गए हैं। मैं उस तूल में जाना नहीं चाहता। इसपर आपस में बहुत विवाद हो चुका है। मैं तो केवल इसलिए इसका समर्थन करता हूँ कि यह विधेयक पहले ही कश्मीर में लागू कर देना चाहिए था, किन्तु संविधान का आर्टिकल 370 जो है उसके कारण कश्मीर की एक स्पेशल स्थिति होने के कारण उस समय इसको लागू नहीं किया गया था और पूरे हिन्दुस्तान में इसको लागू किया गया था। यह एक लैक्यूना रह गया था। कश्मीर हमारा एक सेंसिटिव पार्ट है और वह हमारे देश का अभिन्न अंग है। वहाँ पर ऐसी कार्यवाहियाँ सुनने में आती हैं और अखबारों में पढ़ने में आता है जिससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान की गिद्ध दृष्टि उस पर लगी हुई है और अभी 15 तारीख को आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर पाकिस्तानी जंडे फहराए गए और वहाँ पर पाकिस्तान की मांग करने वाले शायद कुछ लोग मौजूद हैं जो आतंकवादी गतिविधियों से देश की अखंडता को खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए ऐसी सूरत में ऐसी पाकिस्तानी कार्यवाहियों को बंद करने के लिए कश्मीर में इस एक्ट का लागू करना जरूरी था और इसीलिए वह लागू किया जा रहा है।

इस अधिनियम में, जैसा कि संशोधन किया गया है, जो दंड की व्यवस्था की गई है वह बहुत उपयुक्त है। हमारे देश में जो पहले का दंड विधान है उस में हत्या, आगजनी, लूटपाट इत्यादि के लिए कुछ विधान है, लेकिन इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के लिए विधान नहीं था। आतंकवादी गतिविधियाँ क्या हैं इसकी परिभाषा नहीं थी। इसमें इसकी परिभाषा की गई है और उसके लिए दंड की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत उचित है। उसमें हत्या के आरोप में आपने आई० पी० सी० के अधीन कारावास का दंड रखा था, किन्तु आतंकवादी गतिविधियों के कारण यदि कोई हत्या की जाती है और आतंकवादी के खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे केवल मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी, यह प्रावधान इसमें रखा गया है। ऐसा करने से लोगों को मालूम होगा कि अगर आतंकवाद से हत्या होने का आरोप सिद्ध हो जाएगा तो मृत्युदंड ही मिलेगा। ऐसी जानकारी लोगों को होनी चाहिए और इसलिए दंड का जो विधान रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

इसके अलावा और दूसरी जो गति-विधियाँ हैं जिनमें विध्वंसात्मक कार्यवाही होती है तो उसके लिए तीन साल की सजा कम से कम और आजन्म कारावास की सजा रखी गई है। इसी तरह से अगर हत्या की साजिश करना या हत्या के लिए उत्तेजित करना या हत्या के काम के लिए प्रेरित करने की जहाँ तक बात है, ऐसे आरोप सिद्ध होने पर उस व्यक्ति को कम से कम पाँच साल की सजा और अधिक से अधिक आजन्म कारावास की सजा दी जा सकती है। यह अच्छा कदम है। हमारे देश में जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं उनको कड़ाई के साथ रोकने के लिए यह प्रावधान बहुत उत्तम है और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

हिंसा की राजनीति प्रजातंत्र में लागू नहीं होती। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी मांगों चाहे वे आधिक हो या राजनीतिक रखने का अधिकार होता है।

जो विविध जन हैं देश में उनको अधिकार हैं कि वे अपनी मांगों को रखें लेकिन उनमें हिंसा का समावेश होना दुखदायी है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आन्दोलन शुरू होते हैं तो उनमें आगे चलकर कुछ असामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं और वे देश की सम्पत्ति और जीवन के हितों का ध्यान नहीं रखते। इससे जनतन्त्र को बड़ा नुकसान पहुंचता है। आंदोलनकारी अपनी मांगे मनवाने के लिए आन्दोलन करते हैं, लेकिन उस आन्दोलन में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। वह आन्दोलन अहिंसक होना चाहिए। पंजाब में हमने देखा कि अकालियों ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक मांगों को लेकर जो आंदोलन किया उसमें कुछ आतंकवादी शामिल हो गए। उन्होंने अकालियों को बदनाम किया, लेकिन बाद में हम अपने नेता राजीव गांधी को धन्यवाद देते हैं कि उनकी सूझबूझ और उदारता के दृष्टिकोण में जो समझौता पंजाब के बारे में लोंगोबाल जी के साथ किया, जिसमें उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, उस से आतंकवाद का पर्दाफाश हुआ और यह मालूम हुआ कि वे समाजविरोधी तत्व थे जो बाहरी ताकतों के सहारे पंजाब में उत्थात कर रहे थे और अब वे अलग-थलग पड़े हुए हैं। इस तरह से पंजाब में जो आतंकवादी गति-विधियाँ थीं उनकी जड़ में कुठाराघात करने का प्रयास किया गया है। वह एक प्रशंसनीय कदम है और इसलिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण काम किया और अपने देश की अखंडता और एकता की रक्षा करने के लिए कदम उठाया। उसके लिए वे हम सबके धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूँ कश्मीर में जो विघटनकारी तत्व और आतंकवादी तत्व हैं इस विधेयक के पास होने के बाद उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। आपने इस संबंध में

[श्री केशव प्रसाद शुक्ल]

बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ ।

SHRI YALLA SESI BHUSHANA RAO (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, the Government has now introduced this Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Amendment Bill to enlarge the scope of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act which we passed in last March to the State of Jammu and Kashmir. Madam that was the time when the terrorist movement was at its height in the country and everybody said that some steps were necessary to crush the terrorist. Likewise, we also appealed that instead of mere Acts, it is necessary to have politico-socio-economic settlement here. Likewise, our Prime Minister rightly sought an agreement with the Akalis and he defused the terrorist activities there. But mere enactment of legislation or passing this Bill cannot prevent the terrorists as they are a mad lot, a desperate lot and we cannot prevent their activities through a political settlement only. We can only defuse the situation. Still the terrorist danger is there in the country.

* Madam, my humble submission is that we miserably failed in preventing the terrorist activities. That is why we lost the precious life of our Prime Minister. Then there were the bomb blasts in Delhi. And after the passing of the legislation, the latest one was that our MP, Shri Lalit Maken, along with his wife was shot dead brutally in open daylight in the Capital. So, there is something lacking in our Police Force and in our Intelligence Force, and drastic changes are necessary in the Intelligence and the police Force. We say that you punish a terrorist deterrently. But a terrorist who is a misguided youth, is prepared for his life and he is not afraid of anything. So, this is necessary to prevent such a thing and social consciousness is necessary and awareness in the people is necessary in order to see that terrorists are eliminated. Then there is another as-

pect, Madam, I humbly submit that there is an intelligence report that we lost the precious life of our Prime Minister in Delhi there are hundreds of terrorists who came across the border to Delhi in order to do some mischief in the Capital before the 15th August. It is a fact. It has been revealed in the reports of the Intelligence Department. But unfortunately not even one terrorist has been traced uptill now. What has happened to these hundred terrorists? So it is clear that there is some lethargy, there is some inaction, there is some wrong in the police machinery. We have therefore, to see and the Government has to see that the police machinery and the intelligence machinery become more alert.

Madam Deputy Chairman, by this Amendment Bill we are extending the Act to the State of Jammu and Kashmir. Kashmir is an important border State. They have got a sensitive appeal also. But in Kashmir the Government has committed a grave mistake. In Kashmir there is no people's Government. It has to be corrected. In mistake, the previous Government, and there is a grave mistake in the Government. It is not the wish of the people. We passed an Anti-Defection Bill. We wanted clean politics in the country. But the whole Cabinet is a defector Cabinet and nobody can say that there is a legitimate Government. Technically one can say that there is a Government but it is a puppet Government.

SHRI DEBA PRASAD RAY (West Bengal): On a point of order, Madam, what has happened in Kashmir was not defection. Even as per the Anti-Defection Bill, that has been interpreted as... (Interruptions).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shawl, his point of order is addressed to the Chair. (Interruptions). Either you should decide or I should decide. No, you please sit down. Mr. Shawl you have already spoken. If a Member has to ask something on a point of order, it is for the Chair to decide. Please sit down. (Interruptions). It is all right. Let him make his point.

Kashmir people say that it is a splinter Government. But this is the land of Mahatmaji. This is the country of some moral values. Are we conscious that it is a defection or moral turpitude, selling of the people to one Government? In this way the country will not flourish. What we speak, we must act on. I feel that every Member of the other side if they think correctly and conscientiously they can appreciate it. Definitely I wish our Prime Minister, who is expecting clean politics, will do something on this sensitive issue so as to usher in a new Government in Kashmir and have elections on the basis of the will of the people and let them decide. With these words, Madam, I say that prevention of defection and cleanlines in politics is necessary and proper reorganisation of police is necessary. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN. Shri Hashim Raza Abidi Allahabidi—not present. Shri Sukhdev Prasad.

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : मैडम डिप्टी चेयरमैन, आज जो बिल हाउस में पेश हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैंने अपने विभिन्न साथियों के विचार सुने। उनके विचारों से यह लगा कि एक बात तो सर्वसम्मत है कि इस बिल को जम्मू काश्मीर में लागू करने का औचित्य है। लेकिन जो शंकाएँ हमारे साथियों ने प्रकट कीं, उससे यह लगता है कि जब से यह ऐक्ट लागू हुआ तब से इसमें बहुत सारी गड़बड़ी पैदा की गई। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब पिछले साल आपका बिल पास हुआ और उसके बाद वह लागू हुआ तब से लेकर अब तक कितनी गड़बड़ाइयाँ इसके तहत हुई हैं? मैं समझता हूँ कि कोई माननीय सदस्य इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई इस बात का सबूत दे कि इसका कहीं मिसयूज हुआ हो। तो फिर जब बिल का अमेंडमेंट जम्मू-काश्मीर तक ले जाते हैं तो फिर इस में शुबाह की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। मेरे बहुत सारे साथियों ने इस बात को उठाया और इस बात की शुबाह पैदा की कि इसका मिसयूज होगा और जम्मू-काश्मीर में

इसको लागू नहीं किया जाना चाहिये। यह बिल गलत है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूँ जो मुक्त के अन्दर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं और उस बिल को जो लागू किया गया, उसके तहत गिरफ्तारियाँ हुई, बहुत सारे लोग मारे गये तो क्या आप यह समझते हैं कि रूलिंग पार्टी के ही लोग मारे गये या वहाँ आतंक में हमारी जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के नेता या दूसरे हमारी पार्टियों के नेता मारे गये? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सभी पार्टियों के लोग मारे गये। अगर दो राय नहीं है तो इसमें शुबाह करने की कोई गुंजाइश नहीं। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि जम्मू-काश्मीर में इसे क्यों लागू किया जा रहा है, इसके औचित्य के बारे में और अधिक नहीं कहना है। लेकिन मैं यह चीज अपने काश्मीर के शाल साहब से जो मेरे साथी हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस बात के लिये बहुत जोर दिया है कि यह करप्ट गवर्नमेंट है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह वे जो गुल शाह के समय में कांड हो रहे हैं क्या इसके पहले कभी नहीं हुए? हमारे हाकी के प्लेयर जो दूसरे देश के साथ मैच खेल रहे थे उनके साथ वहाँ क्या तमाशा हुआ? क्या यह गुल शाह के समय में हुआ? काश्मीर शहर में जो बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियाँ हुई उसमें कितने ही लोग मारे गये उस समय क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या इसमें गुल शाह सरकार की सारी जिम्मेदारी थी? मैं दूसरी चीज यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात को नहीं महसूस करते हैं कि जो पाकिस्तान में आतंकवाद का प्रशिक्षण हो रहा है जो उनको तालिम दी जा रही है वे यह कर पंजाब के रास्ते, राजस्थान के नाते, काश्मीर के नाते हमारे देश में हिडरेंस पैदा नहीं कर रहे हैं? अगर वे हिडरेंस पैदा कर रहे हैं तो क्या हमारा यह फर्ज नहीं है कि हम साईचिन के लिये उन पर दबाव डाल सकें? पाकिस्तान से मिल कर, काश्मीर के जो हमारे बहुत से नाजुक प्वाइंट हैं उनके बारे में उन पर दबाव डाल सकें? अगर हम उनके बचाव के लिये, अपने हिस्से को बचाने के

[श्री सुखदेव प्रसाद]

लिये, आतंकवाद के खिलाफ कोई बिल लाते हैं, कोई कानून पास करते हैं तो क्या गुनाह करते हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि मुल्क के अन्दर जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही थीं, आज मुझे खुशी है हमारे युवा प्राइम मिनिस्टर ने किसी तरह से उन पर काबू पाया और काबू पाने के साथ-साथ आज मुल्क राहत की सांस ले रहा है, पंजाब राहत की सांस ले रहा है, असम राहत की सांस ले रहा है और कुछ और छोटी-मोटी चीजें होंगी, मेरा ख्याल है कि उनकी सूझबूझ से सारे मामले हल हो जायेंगे।

जहाँ तक मुल्क में ला एंड आडर का प्रश्न है इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादी आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में अपना पंजा जमा रहे हैं। शायद कोई मुल्क ऐसा बचा हो जिसमें आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियाँ तेज न की हों। हर मुल्क अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस तरह का कानून उनके खिलाफ पास कर रहा है, उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। उसी के तहत हिन्दुस्तान भी अपने कानून बना कर मुल्क के अन्दर एक्शन ले रहा है और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। —इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ साथी भले ही कुछ बातों में मतभेद जाहिर करते हों, लेकिन जहाँ तक इस बिल की मंशा है, उससे वे सहमत होंगे।

श्री धर्मबन्ध प्रशस्त (जम्मू और काश्मीर) : उसभाषित महोदया, आज जो विधेयक सदन में पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। यह अच्छा किया गया है। यह विधेयक जम्मू-काश्मीर पर भी लागू किया गया है। लेकिन मुझे इसमें शंकाएँ हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि वे उनका कुछ समाधान कर दें। आर्टिकल 370 के अन्दर कोई भी विधेयक वहाँ पर पेश होता है तो वह वहाँ लागू नहीं होता

है। यह एक दो विधेयक है जिसमें यह लिखा है कि This will not apply to Jammu and Kashmir. मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाकी विधेयकों में आपने यह क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब यह है कि बाकी विधेयक जब वहाँ पर पास हो जाते हैं तो वे वहाँ पर लागू हो जाएंगे। सिर्फ यही विधेयक वहाँ पर लागू नहीं होगा मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। सन् 1975 में अब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो वह जम्मू काश्मीर पर भी लागू हो गई थी। मैं समझता हूँ कि उस वक्त उस बिल में यह नहीं लिखा था कि यह जम्मू-काश्मीर पर लागू नहीं होगा। जब इस विधेयक के बारे में कुछ नहीं लिखा गया तो यह समझा गया कि जम्मू-काश्मीर में टेरोरिज्म, आतंकवाद नहीं है, इसलिए वहाँ पर लागू नहीं हो रहा है। बाद में हमारे संसद-सदस्य श्री घावे जी ने पूछा तो कानून मंत्री जी ने बताया कि यह विधेयक आर्टिकल 370 के अन्दर लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 370 के अन्दर कोई भी बिल लागू नहीं होगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यह जो आर्टिकल 370 है, जिस वक्त यह आर्टिकल पास हुआ, when it was incorporated into the constitution of india यह डाफ्ट कांस्टिट्यूशन में नहीं था। उस वक्त सेन्टर में श्री गोपालस्वामी आयोगर मिनिस्टर थे। वे जम्मू-काश्मीर में छः साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। बड़े कम्पोजेंट प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने वजा तौर पर कहा कि यह जो आर्टिकल 370 हम रख रहे हैं यह टेम्परेरी और ट्रांजिसनल है। इस वक्त जम्मू काश्मीर का केस यू०एन०ओ० में है। जैसे ही वहाँ से यह मामला हट जाएगा, यह आर्टिकल भी हट जाएगा। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अब आप इसको कितने साल तक टेम्परेरी दर्जा देना चाहते हैं? इसकी लिमिट कितनी है? स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से एक संसद सदस्य ने पूछा था कि इस धारा को आप उड़ा क्यों नहीं देते हैं? उन्होंने कहा कि यह घिसते-घिसते घिस जाएगा। श्री गोपालस्वामी आयोगर ने कहा था कि यह टेम्परेरी और ट्रांजिसनल है। पाँच

साल पहले शेख अब्दुल्ला ने जब वे जम्मू-काश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे ऐसेम्बली के अन्दर लिखित बयान में कहा था कि This article is not sacrosanct. इस आर्टिकल में दो चीजें हैं। एक जम्मू काश्मीर का स्पेशल दर्जा है और एक इसकी नागरिकता का सवाल है। जहाँ तक स्पेशल स्टेटस का संबंध है, मैं इसके विषय में नहीं कहूँ। यह रहे। यह इसलिए नहीं कि यह मुस्लिम मेजोरिटी का स्टेट है, बल्कि इसलिए कि यह बैकवर्ड स्टेट है, पाकिस्तान से घिरा हुआ है। यह स्पेशल स्टेटस रहे बेशक, लेकिन नागरिकता का सवाल हमारे सामने है। उस दिन गृह मंत्री जी ने कहा था कि सारे भारत की नागरिकता एक है। जम्मू काश्मीर में यह स्थिति नहीं है। बाहर का कोई भी आदमी वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है, भारत का कोई नागरिक वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है चाहे वह राष्ट्रपति ही क्यों न हो। एक इंच जमीन भी नहीं खरीद सकता है। आप मुनिये, बाद में बोलिये।

उसके बाद इसकी जो नागरिकता है वह यह है कि 1947 में जितने लोग पाकिस्तान से भारत में चले आये तो वे वहाँ के नागरिक हो गये। लेकिन वहाँ से उन्हें बाहर जाना पड़ा क्योंकि वे वहाँ रह नहीं सकते थे। लेकिन 30 हजार हरिजन परिवार वहाँ आकर सेट हो गये। वे वहाँ 37 सालों से सेटल हैं वहाँ बैठे हुए हैं, बाडर पर हैं, लेकिन वे वहाँ के नागरिक नहीं हैं। 37 साल पहले जो व्यक्ति आया था, उसके लड़के हुए, लड़के के भी लड़के हुए, तीन जनरेशंस हो गई हैं, लेकिन वे वहाँ के नागरिक नहीं हैं। वे वहाँ पर कोई सरकारी ठेका नहीं ले सकते हैं, वे कितना इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते हैं, चाहे वह पार्लियामेंट हो, चाहे असेम्बली हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे म्युनिस्पैलिटी कमेटी हो, वे कहीं भी वोट नहीं दे सकते। यह इसलिए कि वे वहाँ बाहर से आये हैं। अब जैसे एक लड़की है, उसकी शादी रियासत से बाहर हो जाती है तो इसमें उसके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं उसके वहाँ नागरिकता के जो सारे अधिकार हैं, जायदाद के जो अधिकार हैं वह बिल्कुल

खत्म हो जाते हैं। अगर लड़की विधवा हो जाय तो जब तक वह रियासत में दूसरी शादी न कर लेतब तक वह वहाँ की नागरिक नहीं रह सकती। ये विषय हैं जो सभी के अन्दर चन रहे हैं। मेरी यह मांग है कि जो बिल आप पास करते हैं उन सब पर आप लिखिये इट बिल नाट अम्पाइड टू जे एण्ड के, यह ट्रांजिशनल टेम्पोरेरी प्रोविजन है, इसका प्रबन्ध कर दिया जाए ताकि पता लगे कि यह टेम्पोरेरी है इसलिये मैं आपसे यही कहूँगा कि जहाँ तक 370 की स्पिट का सम्बन्ध मुझे पता नहीं था। मैंने इस पर तीन किताबें पढ़ी हैं। लेकिन इस पर भी इसकी स्पिट का मुझे नहीं पता था। एक आदमी ने, ही वाच वन आफ दि आर्थर्स आफ दि आर्टिकल 370 उन्होंने समझा तो पता लगा कि इसके अन्दर क्या स्पिट है। अब मुझे पता है। लेकिन मैं भारत सरकार से यह कहूँगा कि आप यह जो 370 आर्टिकल है इसको उड़ा दें। काश्मीर का दर्जा एक स्टेट का रखें। इस 370 आर्टिकल के अन्दर कई हत्याएँ हो रही हैं लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आर्टिकल 370 को हटा दें ताकि वे लोग जो वहाँ रह रहे हैं वे पूरी तरह से वहाँ के नागरिक रह सकें।

SHRI ARIF MOHD. KHAN: Ma-dam Deputy Chairman, I am thankful to the hon. Members who have taken part in the disussion, thankful to those who have supported the Bill and also thankful to those who have criticised and opposed the Bill because they have also enlightened us about many aspects. I am sure that while implementing the provisions of this Bill whatever has been discussed in the House will always be kept in view.

प्रशांत जी ने पूछा है कि कानूनी दृष्टिकोण क्या थी इस विधेयक को उस समय, जब यह बाकी पूरे देश पर लागू हुआ था, उस समय काश्मीर पर लागू करने में। संविधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत यह संसद विधेयक बनाने का

[Shri Arif Mod. Khan]

अधिकार हासिल करती है और उसी के अन्तर्गत यह राय थी कि काश्मीर पर कानून लागू करने के लिये, खासतौर से, आतंकवाद से संबंधित जो धारा है, उसमें जिस एन्ट्री से संसद अधिकार प्राप्त करेगा वह एन्ट्री उसलिस्ट में नहीं है, जिन्हा लिस्ट में हर रियायत की हकूमत का सर्जि के और उनकी राजबन्दी, उनसे सलाह किये बिना हम कानून बना सकें।

The hon. Members have objected and taken exception to this legislation being issued in the form of an Ordinance. Many hon. Members have said that since Parliament was going to meet, where was the need to issue an Ordinance? Madam, I feel that when Parliament had put its seal of approval in the last Session, the Parliament had made its intention known. In fact, I do not know about this hon. House, but in the other House many hon. Members had moved amendments saying that the scope of the Act should be extended to the State of Jammu and Kashmir also. Even Members belonging to the party of Mr. Shawl, also did not object to the scope of the Act being extended to the State of Jammu and Kashmir, though they were critical of the State Government. But Members belonging to the Opposition parties also had demanded this and while responding to the points made by the hon. Members from the Opposition, the Law Minister had assured that it was intended to be done after the Act was passed. The procedure to be followed in achieving the object of extending the whole of the Act to the State of Jammu and Kashmir was considered in consultation with the Ministry of Law and Justice. It was considered that some amendment to the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order 1954 would be required before the Act could be made applicable to that State. Madam, after taking all those steps, which were required, the Ordinance was

issued. This was discussed in very great detail. Today the purpose of coming to Parliament with this legislation is very limited—i.e. to extend the scope of this Act to Jammu and Kashmir State. As far as the main body of the Act is concerned, both Houses of Parliament had discussed it in details and had put their seal of approval of it.

अश्विनी जी ने जिन्होंने शुरुआत की थी मैं उसी की बात से आ रहा हूँ। अश्विनी जी ने भी कहा और भी माननीय सदस्यों ने धारा 370 के बारे में कहा। महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि आज हम धारा 370 पर चर्चा करने के लिए जमा नहीं हुए हैं। आज इस चर्चा का उद्देश्य बहुत सीमित है एक ऐसा कानून जिसके ऊपर दोनों सदन अपनी राय पहले ही दे चुके हैं कुछ संवैधानिक अड़चनों के कारण जिसको हम एक विशेष राज्य तक नहीं बढ़ा पा रहे थे उसके लिए इस सदन की अनुमति लेना, लेकिन हम यह मानते हैं कि यह इससे सम्बन्धित मामला नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान में पूरा चेंटर ही है जो इस स्पेशल और टेम्पोरेरी प्रोविजन से डील करता है और उसमें एक राज्य नहीं है हमारे देश के कई एक राज्य हैं कई एक क्षेत्र हैं जिन के ऊपर इन टेम्पोरेरी प्रोविजंस को लागू किया जाता है लेकिन आज चूंकि उस पर चर्चा नहीं हो रही है इस लिए मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। इसलिए यह जो सवाल किया गया है कि उस धारा को कब तक खत्म किया जाएगा मैं समझता हूँ उसके लिए उचित व्यक्ति में नहीं हूँ कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। मैं तो वही बात दोहराऊंगा जो बात सरकार बार बार कह रही है जो सरकार का स्टैंड है वह यह है कि हम इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। अब एक बात यहां पर तकरीबन सभी दलों से सम्बन्ध रखने वाले माननीय सदस्यों ने जोर दे कर कही है और वह बात यह है कि यह कहा गया कि आतंकवाद को खत्म

करने के लिए केवल कानून से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। बार-बार यह कहा गया है कि पंजाब की समस्या का समाधान अगर बातचीत से हुआ आसाम की समस्या का समाधान हुआ तो बातचीत से हुआ फिर कानून की कथा जरूरत है। मैं यह मानता हूँ पहली बात तो यह है कि इस कानून का उद्देश्य असम समस्या, पंजाब समस्या काश्मीर समस्या या देश के किसी दूसरे क्षेत्र में पनप रही किसी समस्या से निपटने के लिए यह कानून नहीं बनाया गया है।

यह कानून लाया गया है आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए। इसका ऐसी किसी समस्या से कोई संबंध नहीं है जहाँ कोई राजनीतिक भागें रखी गई हों, किसी क्षेत्र के विकास के लिए कोई मांगें रखी गई हों, किसी राजनीतिक दल द्वारा भागें रखी गई हों।

मैं दोनों को मिलाने से इन्कार करता हूँ और मैं यह समझता हूँ और इसलिए यह गौर कर रहा था कि ज्यादा देर तक चर्चा काश्मीर की घटनाओं पर चलती रही, इस विधेयक से संबंधित चर्चा कम हुई।

मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इस विधेयक का उद्देश्य है—किसी क्षेत्र की समस्या को हल करना, उसके लिए दूसरे तरीके हैं और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है हमारे लिए, हम बार-बार दोहराते हैं बातचीत का जरिया। बातचीत के तरीके से अपनी समस्याओं का—लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि किसी क्षेत्र में कोई राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, किसी दल द्वारा अगर ऐसा आंदोलन चलाया गया, उस वक्त जब समाज-विरोधी, हिंसा में विश्वास रखने वाले तत्व आतंकवाद का सहारा लेकर उस मौके का फायदा उठा कर अपराध कर जाते हैं, आतंकवाद की घटनाएं कर जाते हैं, मासूमों की जान ले लेते

हमारे इस विधेयक को लाने का उद्देश्य यही है कि हम इन तत्वों की

कार्यवाइयों को नियंत्रित कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें, उनको रोक सकें।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि बार-बार यह बात की गई है कि बातचीत के जरिए ऐसे मामलों को ज्यादा मुलबाया जा सकता है, सरकार के पास अगर यह शक्ति होगी कि सरकार उन साजिशों का मुकाबला करने की शक्ति रख सके जो साजिशें हिंसात्मक और आतंकवाद के तरीकों से की जा रही हैं, तो फिर शायद उन तत्वों को हम काबू में कर सकें। तो फिर जो सेन एलिमेंट्स हैं, जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए, फिर शायद बातचीत भी ज्यादा कामयाबी से हो सकती है और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है।

काश्मीर के बारे में जो बात हुई, मैं पूरी तरह कार साहब ने जो कुछ कहा है, मेरी पूरी हमदर्दी है उन बातों के साथ, जो आपने कहा, मैं भी यह मानता हूँ कि वह इतिहाद के नज़दीक लाने के, एकता के, इन सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है।

अब माननीय सत्यप्रकाश मालवीय जी कह रहे थे काश्मीर के बारे में, मेरे बारे में कुछ कह रहे थे—वात सही है, मैं अक्सर जाता रहता हूँ और मैं यह महसूस करता हूँ कि जहाँ एक तरफ अखबार में छपने वाली कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ कर चिंता होती है, वहाँ दूसरी तरफ उन लोगों की कमी नहीं है काश्मीर की घाटी में जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि एक नहीं अनेक ऐसी मिसालें हैं, जहाँ विदेशी हमलावरों से मुकाबला भी सादे निहत्थे हाथों से श्रीनगर और काश्मीर के लोगों ने किया, इसलिए कि वह इस बात का तसव्वर भी नहीं कर सकते हिंदुस्तान में अलैहदगी का, उनके दिमाग में कोई तसव्वर भी नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं है और इसलिए उस इतिहाद की, बंधन को हम और मजबूत बनाते चले जाएं।

आपने जो जज्बात का इजहार किया है, मैं उससे पूरी हमदर्दी रखता हूँ और मैं

[श्री आन्फि मोहम्मद खान]

आपकी बात को मुताल्लिक़ा महबूबों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा।

शाल साहब बहुत ज्यादा नाराज थे और कह रहे थे... (अवधान) नहीं, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शाल साहब मेरे साथ बहुत नाराज थे, कह रहे थे कि हमारे साथ—बहुत मौजूदा सरकार के लिए जो कुछ उन्होंने कहा, कहा। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर कश्मीर में कोई वहाँ इलाकाई जमात है, उस जमात में इस्तिहाद बनी रहे, एकता बनी रहे, यह मरकजी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती। यह जिम्मेदारी तो उसी पार्टी के अपने ऊपर आती थी।

अब उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग कहते हैं गुलशाही कर्पू। असल में कश्मीर के लोग बड़े पुर-मजाक हैं और वह बड़े अच्छे जुमले कहते हैं। चन्द दिनों पहले एक लफ्ज़ वहाँ बहुत रायज था—वह भी आपको याद होगा—बहुत दिनों की बात नहीं है और मैं किसी के ऊपर इलजाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ कि कश्मीर के लोग बहुत पुर-मजाक हैं और बहुत अच्छी बात कहते हैं और मैं समझता हूँ कि जिस शब्द के अंदर यह सलाहियत हो कि वह अपने ऊपर हंस सके, वह यकीनन तौर पर आदमी होता है और बुरा आदमी नहीं होता है।

तो वहाँ के लोगों में यह सलाहियत है और मेरा ताल्लुक सिर्फ यही नहीं कि मैं बहुत ज्यादा आता-जाता हूँ, मेरे साथ युनिवर्सिटी में बहुत पड़े हुए मेरे बहुत से दोस्त हैं वहाँ बहुत जगहों पर—पर शाल साहब शिकायत कर रहे थे कि बड़ी ज्यादातियाँ हैं वहाँ... बड़ी ज्यादातियाँ हैं कर्पू के बारे में बात करते हुए हमारे लोगों को जेल में भेजा जाता है, वहाँ ज्यादातियाँ होती हैं। मुझे आज भी वह बात याद है, शाल साहब ने तो जेल की ही बात की है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है अभी दो-ढाई साल पहले की बात है। जाड़े के दिन, दिल्ली में तो जाड़े की

रात में उतनी ठंड होती होगी जितनी उस दिन वहाँ पर दिन की ठंड थी और सुबह दस बजे हमने चलना शुरू किया, अपने जम्हूरी हकूक का मुतालवा करने वालों को सिर्फ जेल नहीं भेजा गया बल्कि डंडे मार-मार कर उनकी जान भी ले ली गई। यह पुरानी बात नहीं है। चाहे आनन्द नाग का शोकांत हो, चाहे बारामुला का खिजर मोहम्मद हो, वह कोई मामूली आदमी नहीं था, बहुत बड़ा किसान था। हर डंडे के साथ उससे कहा गया कि फिर कहो, आजाद हिन्दुस्तान जिदाबाद। वह हर डंडे के साथ आजाद हिन्दुस्तान, जिदाबाद, कहता रहा और डंडे खाता रहा और आखिर में उसने अपनी जान दे दी। यह बहुत पुरानी बात नहीं है। सारे अखबारों में छपा है और तफसीलात में छपा है। मुझे भी इसलिए वह बात याद है कि उस रात इतना जाड़ा था कि मुझे कार में अंगीठी लेकर बैठना पड़ता था। मैं रात को 12 बजे खिजर मोहम्मद के घर पहुंचा। इसलिए मैं उस रात को भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ कि अगर कहीं यह चीज है और अगर आपके लोगों के साथ भी ज्यादातियाँ हो रही हैं, मुझे आपके साथ हमदर्दी है और मैं यह समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री गुलाम मोहिउद्दीन शाल : मैं इतना अर्ज करूँ जहाँ तक इन चीजों का ताल्लुक है हमें तो इतना देखना है कि अगर माजी में कहीं कोई गलती होती है आपने उसके बारे में व्हाइट पेपर भी शायद किया है, गवर्नमेंट आफ जम्मू-काश्मीर लेकिन फारूक या उसके किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिखा गया, because all the charges were baseless.

श्री आरिफ मोहम्मद खान : मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। मैंने सिर्फ यह कहा है कि हमारी सिवासी तहजीब का यह बात हिस्सा नहीं बनना चाहती है, अगर हमारे किसी में सिवासी इख्तलाफात हैं तो हम उसको गैर सिवासी तरीकों से परेशान करने लगे। इसीलिए

मैंने कहा आज आपकी हुकूमत वहाँ नहीं है और आप इसकी शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो मैं आपके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहा हूँ मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि मेरी हमदर्दी सिर्फ इंडिविजुअल मामलों में नहीं है, मेरी हमदर्दी बुनियादी तौर पर इस बात के लिए है कि किसी भी शख्स के साथ ज्यादानी नहीं होनी चाहिए और विल के हाथ से भी नहीं होनी चाहिए। अगर आज हो रही है तो वह भी गलत है। दो साल पहले होती थी तो वह भी गलत है। आईदा के लिए हमें तय करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा इसलिए भी कहा कि इस बिल का मकसद बहुत महदूद है, सीमित है वह है कि जिस प्रकार पालियायो पहले ही अपनी राय का इजहार कर चुकी है, उसका दायरा काश्मीर तक ले जाएँ। माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं और मैंने नोट भी की हैं और मैं फिर भी यह बताता चाहूँगा, शायद माजवीय जी ने पूछा था कि इस बिल के बनने के बाद से कितने राज्यों में कोर्ट्स बने हैं और कितने केसिज का ट्रायल हुआ है। हरियाणा में 4 बने हैं, पंजाब में 4 बने हैं, उत्तर प्रदेश में तीन बने हैं, हिमाचल प्रदेश में दो बने हैं, सिक्किम में एक, चण्डीगढ़ में एक, दिल्ली में तीन और राजस्थान में भी है, इसमें नहीं दिया हुआ है। कुल मिलाकर 40 केसिज हैं। जाहिर है कि इतनी जल्दी अभी यह उम्मीद करना कि उनमें कोई निर्णय हो गया तो अभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ वक्त लगेगा मुकदमों को चलाने में और उनका फैसला करने में। आपके माध्यम से मैं एक बार फिर यकीन दिलाना चाहूँगा कि जब शुरू में यह बिल आया था तो उस समय भी यह शंका व्यक्त की गई थी कि इसका नाजायज इस्तेमाल तो नहीं होगा, इसका राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं होगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और न ऐसा होगा। यह बिल 4 P.M. सिर्फ उन लोगों का सामना करने के लिए है... बीबीवी पर जारी यह बिल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का सामना करने के लिए है, जो आतंकवाद या

हिसा का सहारा लेकर चीजों को प्रभावी करना चाहते हैं। हमारे हाथ उनमें दोस्तों करने के लिए बड़े हुए हैं जो देश की एकता और अखण्डता, देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण, अच्छा माहौल बनाने का काम करने के लिए तैयार हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, उनसे हाथ मिलाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अपने हाथ में ताकत भी रखना चाहते हैं ताकि उन अन्धसर का, उन तत्त्वों का भी मुकाबला किया जा सके, जो आतंकवाद या हिसा का सहारा लेकर इस देश की एकता या अखण्डता को कमजोर करने की कोशिश करें, हमारे देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश करें। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इस पर अपना पूरा समर्थन देंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That this House disapproves of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Amendment Ordinance... 1985 No. 4 of 1985) promulgated by the President on the 5th June, 1985."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Arif Mohd. Khan to vote. The question is:

"That the Bill to amend the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1985, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARIF MOHD. KHAN: I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE AUROVILLE (EMERGENCY PROVISIONS) AMENDMENT BILL, 1985

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Auroville (Emergency Provisions) Amendment Bill, 1985. Shri K. C. Pant.

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI K. C. PANT): Madam, I rise to move that the Bill to amend the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980, be taken into consideration.

Madam, before the House begins a discussion on the Bill, I think it would be useful if the background of this proposal is briefly placed before the hon. Members. The International cultural township known as 'Auroville' was set up in 1968 where people of different countries could live together in harmony and in one community, who were expected to engage in cultural, educational and scientific and other pursuits. At the initiative of the Government of India, UNESCO passed resolutions in 1966, 1968 and 1970 commending Auroville to those interested in UNESCO's ideals and inviting its Member-States and international governmental and non-governmental organisations to participate in the development of Auroville as an international cultural township to bring together the values of different cultures and civilisations in a harmonious environment with a decency for living which correspond to man's physical and spiritual needs. Funds for the development of Auroville were provided by different organisations in and outside India. Substantial grants were also made for the purpose by our Central and State Governments. Sri Aurobindo Society, a non-governmental organisation, was a major channel for these funds. The society is quite distinct from Sri Aurobindo Ashram and Auroville.

Serious problems arose after the Mother left her body in 1973. The complaints were subsequently received with regard to misuse of funds by Sri Aurobindo Society and a Committee was set up in 1976 under the Chairmanship of Lt. Governor of Pondicherry to enquire into the same. After a detailed scrutiny of the amounts of Sri Aurobindo Society as also a report of the Audit team, the Committee found instances of serious irregularities in the management of the said society, mis-utilisation of its funds and their diversion to other purposes.

Since the Government of India was interested in the orderly and systematic development of Auroville, it made several attempts to bring about an amicable solution to various problems and disputes. However, as serious difficulties had arisen with regard to the management of Auroville, the President of India, promulgated an Ordinance on the 10th of November, 1980 to provide for taking over, in the public interest, of the management of Auroville for a limited period. The Auroville Ordinance was subsequently replaced by the Auroville (Emergency Provisions) Act, on the 17th December, 1980. The Auroville Act vested the powers of management of the property relatable to Auroville in the Central Government for a maximum period of five years. Initially, the take over of the management was for a period of two years from the 10th of November, 1980 but it has been extended on year to year basis upto November, 1985. Under the provisions of the Act, however, Shri Aurobindo Society challenged the take over of the management by the Government of India in the High Court of Calcutta and later, in the Supreme Court. Because of the interim directions given by the Supreme Court, the Act could not come into full operation until November, 1982 when the Supreme Court upheld the validity of the Act. Thus, a period